नीरा राडिया कांड के दाग़ी सुनील अरोड़ा को.....

पेज एक का शेष

जरिये मुफ्त या कौडियों के मोल बांटी गयी...यह भी टेलीफोन टैपिंग में सामने आ गयी ह''।

आलोक तोमर अब नही रहे पर अपने अंतिम दिनों तक उन्होंने जिस खांटी पत्रकारिता का परिचय दिया था आज वह दुर्लभ है। वो बताते हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री के तौर पर अनंत कुमार से नीरा राडिया की गहरी दोस्ती थी। इसी अंतरंगता का सहारा ले कर नीरा राडिया की सिर्फ एक लाख रुपए की लागत से एक पूरी एयर लाइन चलाने का लाइसेंस उन्हें मिलने वाला था। उस वक्त सुनील अरोड़ा एएसी के निदेशक थे जो इंडियन एयरलाइंस के प्रबंध निदेशक और नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संयुक्त सचिव भी थे।

आलोक तोमर लिखते हैं कि सुनील अरोड़ा ने अनंत कुमार के निर्देश पर राडिया की हास्यास्पद फाइल को रद्दी की टोकरी में डालने की बजाय सिर्फ कुछ मासूम से स्पष्टीकरण मांगे। बाद में अरोड़ा ने सफ़ाई में कहा कि उदारीकरण का दौर था और ऐसे में प्रतियोगिता होती हैं और कई कंपनियां आती हैं, मगर उनकी पात्रता पर मौजूद नियमों और निर्देशों के हिसाब से विचार किया जाता है।

नीरा राडिया ओर सुनील अरोड़ा के रिश्तों पर प्रसिद्ध पत्रकार शांतनु गुहारे ने भी बहुत कुछ लिखा है जिसे आज पढ़ा जाना चाहिए। अपने एक पुराने लेख में वो कहते हैं, ''बातचीत के टेप राडिया का संबंध सुनील अरोड़ा से भी साबित करते हैं। अरोड़ा राजस्थान में तैनात आईएएस अफसर हैं जिन्होंने राडिया को अलग-अलग मंत्रालयों में तैनात अपने दोस्तों तक पहुंचाया। इन टेपों में रिकॉर्ड बातचीत उन नोट्स का हिस्सा है जो सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपे हैं. ऐसा लगता है कि नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल पटेल के खिलाफ मोर्चा खोलकर इंडियन एयरलाइंस के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की अपनी कुर्सी गंवाने वाले अरोड़ा ने राडिया के लिए भारत में कई दरवाजे खोले। यह पता चला है कि इंडियन एयरलाइंस के मुखिया के तौर पर अरोड़ा के कार्यकाल के दौरान सात विमान उन कंपनियों से लीज पर लिए गए थे जिनके एजेंट के तौर पर राडिया की कंपनियां काम कर रही थीं। वरिष्ठ आयकर अधिकारी अक्षत जैन कहते हैं, 'हमारे पास सबूत हैं कि राडिया की कंपनी ने अरोड़ा के मेरठ स्थित भाई को काफी पैसा दिया है'।

ये लेख ओर इस तेवर की पत्रकारिता ज्यादा पुरानी नही है, यह आज से सात आठ साल पुरानी ही बाते हैं, लेकिन अब इन बातों को कोई याद नही रखना चाहता।

FASHION.IN

Available all types of
ladies cotton kurties, Fancy Kurties,
Jegin, legin, Fancy Top,
T-Shirts, Trousers and imported material
in wholesale price.

SPECIALITY IN FANCY TOP & FANCY KURTIES

लेडीज कपड़ों पर भारी छूट
एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।

Address : 5M/22, N.I.T. FARIDABAD NEAR DAYANAND WOMEN COLLEGE, ST. JOSEPH CONVENT SCHOOL ROAD . 9911489490

गरीब को क्या चाहिए

"गरीब को क्या चाहिए.. ?"
"पटेल की मूर्ति.. ।"
"भूखे को क्या चाहिए.. ?"
"शिवाजी की मूर्ति.. ।"
"बेरोजगार को क्या चाहिए.. ?"
"राम की मूर्ति.. ।"
"किसान को क्या चाहिए.. ?"
"बुलेट ट्रेन .. ।"
"अनपढ़ को क्या चाहिए.. ?"
"प्रयागराज ।"
"देश को क्या चाहिए.. ?"
"विश्व गुरु का तमगा.. ।"
"बेघर को क्या चाहिए.. ?"
"राम मंदिर... ।"

सुधी पाठकों से अपील

31 वर्षों से 'मज़दूर मोर्चा' वैकल्पिक मीडिया के तौर पर अपने सुधी पाठकों को वह समाचार, विचार एवं जन उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करता आ रहा है जिसे अन्य मीडिया छिपाने का प्रयास करता है। सुधी पाठक इतना तो समझ ही गये होंगे कि यह छोटा सा अखबार किसी भी राजनीतिक अथवा व्यवसायिक धड़े से जुड़ा नहीं है। जनहित में जो भी प्रकाशित करने लायक सामग्री हो पाती है उसे लोग़ों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है।

बिना विज्ञापनों के, केवल पाठकों के सहयोग से चलने वाला यह छोटा सा अखबार आपको और अधिक बेहतर व निरंतर सेवा देता रहे इसके लिये आप से निवेदन है कि इसमें अपना आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। 'मज़दूर मोर्चा' नियमित रूप से खरीदकर पढ़ने वाले पाठक तो अपना योगदान दे ही रहे हैं, इलेक्ट्रोनिक माध्यम से अखबार पढ़ने वाले पाठकों से विशेष अनुरोध है कि वे भी इसमें अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करें। वार्षिक सहयोग के तौर पर 100-500 रुपये, 1000 रुपये की धनराशि सामर्थ्य अनुसार 'मज़दूर मोर्चा' के निम्नलिखित खाते में डाले जा सकते हैं।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में
खाता संख्या : 451102010004150
IFSC CODE : UBIN0545112

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें:

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. आनंद मैगजीन सैंटर केसी रोड, एनएच-5
2. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड
3. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
4. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे
5. राम खिलावन बल्लबगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने
6. हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास
7. जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207

गतांक की चीर-फ़ाड़

किसान मुक्ति की दिशा

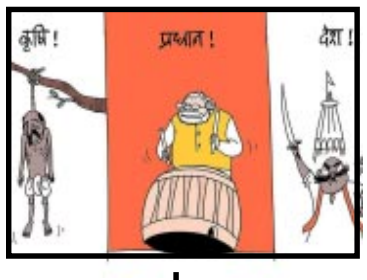

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

मज़दूर मोर्चा के 25 नवम्बर-01 दिसम्बर 2018 के अंक में राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक व आर्थिक मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण समाचार प्रकाशित हुए हैं। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं नगर समिति, नगर परिषद, नगर निगम आदि में जनता द्वारा चुने हुये सदस्य व चेयरमैन, अध्यक्ष तथा मेयर शक्शिाली होते हैं जबकि सरकार द्वारा नियुक्त सैक्रेटरी व कमिश्नर शासक नहीं बल्कि सदन के निर्णयों को कार्यान्वित करते हैं। लेकिन अपने निजी स्वार्थों व हितों को साधने के लिये चुने हुये पार्षद जनता द्वारा प्रदत्त ताकत को कमिश्नर व सत्ताधारी नेताओं के पास गिरवी रख देते हैं और अपनी पसंद का मेयर व डिप्टी मेयर तक नहीं चुन सकते। इसलिये मेयर व कमिश्नर इन जन प्रतिनिधियों की कोई परवाह नहीं करते, जिसका 'नगर निगम सर्कस में 40 पार्षदों को नचा रहा है रिंग मास्टर बन कमिश्नर शाईन' बेबाक विवेचन किया गया है।

स्थानीय कमिश्नर मोहम्मद शाईन अपने आपको इतना शक्तिशाली समझते हैं कि वह सदन व पार्षदों को कोई महत्व नहीं देते। नियमानुसार सदन की बैठक एक महीने में कम से कम एक बार होनी चाहिये और दो बैठकों में 90 दिनों से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिये। ध्यान रहे कि 26 जून 2018 को सदन की आखिरी बैठक हुई थी। पांच महीने बाद 22 नवम्बर को बुलाई गई बैठक में कमिश्नर शाईन के उपस्थित न होने पर बैठक की तिथि 26 नवम्बर की गई। इस बैठक में कमिश्नर शाईन द्वारा नियुक्त सलाहकार पर फ़ाइलों पर बेवजह ऑबजेक्शन लगाने के आरोप लगाये गए। कमिश्नर ने अपने सलाहकार का बचाव करते हुये कहा कि सलाहकार के आने सें करोड़ों रुपयों की बचत हुई है और कई भ्रष्टाचार पकड़ में आये हैं। परंतु पार्षदों ने कमिश्नर की किसी भी दलील पर ध्यान नहीं दिया और सदन में एकजुट होकर सलाहकार को हटाने का प्रस्ताव पास कर दिया। पार्षदों को अहसास हो जाना चाहिये कि वास्तविक शक्ति जन प्रतिनिधियों के पास होती है न कि नौकरशाहों के पास।

मोदी सरकार व भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के आगे सभी संवैधानिक संस्थाएं जैसे न्याय व्यवस्था, सीबीआई, सीवीसी, आरबीआई, ईडी,चुनाव आयोग आदि बेबस हैं जिन्हें इनके द्वारा निर्देशित लाईन पर चलना पड़ता है, जिसका 'अमितशाह के आगे बेबस सीबीआई ने दिया अपने इतिहास का सर्वाधिक हास्यास्पद कानूनी तर्क' में पर्दाफ़ाश किया गया है। जब सीबीआई के जज लोया को खरीदा नहीं जा सका तो अमितशाह के दबाव में लोया को हटाकर एक 'अनुकूल' जज लगाया गया जिसने सनसनीखेज हत्या के मामले में चार्ज लगने के स्टेज पर शाह को डिस्चार्ज करते हुए टिप्पणी की कि अमित शाह को राजनीतिक कारणों से मामले में अभियुक्त बनाया गया है। आश्चर्य यह है कि उस स्टेज पर न तो कोई गवाही हुई थी और न ही केस फ़ाईल पर ऐसे कोई सबूत थे जिसके आधार पर ऐसी कोई न्यायिक टिप्पणी की जा सके। सीबीआई ने हास्यास्पद दलील देते हुये अपील करने से इनकार कर दिया और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी कन्नी काट गये। जज लोया की विवादास्पद मृत्यु की जांच के लिये दायर याचिका भी हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दी गई। इस प्रकार मोदी सरकार द्वारा शाह को बचाने में स्पष्ट तौर पर न्याय की हत्या कर दी गई।

मुंबई की सीबीआई स्पेशल कोर्ट में सोहराबुद्दीन-तुलसी एनकाउंटर केस में चल रही सुनवाई के दौरान मुख्य अनुसंधान अधिकारी (चीफ़ आई ओ) संदीप तामगड़े रोज नये-नये खुलासे कर रहे हैं। 'सोहराबुद्दीन-तुलसी फ़र्जी एनकाउंटर के मुख्य षडयंत्रकारी अमितशाह और तीनों आईपीएस थे-चीफ़ आईओ' में संदीप तामगड़े द्वारा सोहराबुद्दीन व तुलसी एनकाउंटर केस की तफ़तीश के बाद पेश चार्जशीट पर संदीप व बचाव पक्ष के वकील के बीच हुई जिरह का विवेचन किया गया है। इसके अनुसार सोहराबुद्दीन, कौसरबी औ तुलसी की हत्या के मुख्य षडयंत्रकारी अमितशाह, आईपीएस डीजी वंजारा, राजकुमार पांडियन और दिनेश एमएन थे। राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया, मार्बल व्यवसायी विमल पाटनी, हैदराबाद के आईपीएस सुब्रमण्यम और एसआई श्री निवास राव के खिलाफ़ भी चार्जशीट पेश की गई थी। गौरतलब है कि गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हरेन पांड्या हत्याकांड मामले में आजम खान नामक गवाह ने कोर्ट को बताया कि ''हरेन पांड्या को मारने की सुपारी पूर्व आईपीएस डीजी वंजारा ने सोहराबुद्दीन को दी थी। इस बयान से महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है कि जब वंजारा और पांड्या के बीच कोई दुश्मनी न हो तो वंजारा पांड्या की हत्या की सुपारी सोहराब्दीन को क्यों देगा? इस हत्याकांड के पीछे अमित शाह का भी हाथ होने का शक किया जा रहा है।

हरियाणा में भाजपा की मनोहर लाल खट्टर सरकार तथा केन्द्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गूजर द्वारा हरियाणा व फ़रीदाबाद में घोषणाओं व नींव पत्थर रखने के अलावा कोई ठोस कार्य नहीं किया गया बल्कि झूठ पर झूठ बोलकर जुमलेबाज़ी करके लोगों से तालियां बजवाई गई, जिसका 'झूठ बोने कव्वा काटे काले कव्वे से डरियो-960 करोड़ की कौशल यूनिवर्सिटी, 36 करोड़ का अस्पताल तथा आधुनिक स्कूल की आधारशिला रखी' में भंडा-फ़ोड़ किया गया है। खट्टर सरकार द्वारा स्वास्थ्य व शिक्षा के मद पर बजट में कमी की जा रही है। नए अस्पताल की बात कर रहे हैं, वर्तमान में जो सरकारी अस्पताल व डिस्पेंसरी है वहां पर्याप्त स्टाफ़, डॉक्टर व उपकरण नहीं है। करोड़ों रुपयों की लागत से तैयार शहर के एनआईटी स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज व हास्पिटल में पीपीपी मॉडल के तहत चल रही आईसीयू सेवा बंद कर दी गई है। सरकारी स्कूल व कॉलेजों में न तो पर्याप्त स्टाफ़ है, न विद्यार्थियों के लिये बैठने, पेयजल व शौचालय की उचित व्यवस्था है। इस कटु सत्य से भ्रमित करने के लिये कौशल यूनिवर्सिटी खोलने, नया अस्पताल बनाने और सरकारी स्कूल को प्राइवेट स्कूल जैसा आधुनिक स्कूल बनाने के सब्जबाग दिखाये जा रहे हैं।

देश की एक और एयरलाइंस नरेश गोयल की जेट एयरवेज वित्तीय संकट के कारण डूबने के कगार पर है और पंजाब नेशनल बैंक से लिये गये कर्ज की वसूली भी खतरे में है, जिसका 'जेट एयरवेज अगर टाटा ने न खरीदा तो क्या होगा लाला-बैंक और मोदी सरकार का निकलेगा दिवाला मोदी सरकार लोक सभा चुनाव के मद्देनज़र टाटा पर जेट एयरवेज की सम्पत्ति खरीदने के लिये दबाव बना रही है। अन्यथा कहीं नरेश गोयल भी विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की तरह सारा पैसा डकार न ले और खुद दुबई या लंदन में बैठा रहे।

रिजर्व बैंक इंडिया (आरबीआई) की सरप्लस पूंजी लेने के लिये मोदी सरकार व आरबीआई के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनज़र आरबीआई बोर्ड की मीटिंग में हुये निर्णय का 'राम नाम की लूट है, हो सके तो रिजर्व बैंक को जी भरकर लूट-रिजर्व बैंक की सरप्लस पूंजी से कई और विजय माल्या, कई और नीरव-मेहुल चौकसी पैदा करने की तैयारी-3.7 लाख करोड़ के नये बैंक कर्ज आरएसएस और बीजेपी समर्थक उद्योगपतियों को बांटे जाएंगे' में सटीक विश्लेषण किया गया गया। इस निर्णय के अनुसार आरबीआई अपनी सरप्लस पूंजी का हिस्सा मोदी सरकार को उपलब्ध करायेगा जिससे बैंक 3.7 लाख करोड़ रुपये के नये कर्ज दे पायेंगे और लघु मध्यम उद्योगों को कर्ज देने की शर्तों में ढील दी जायेगी तथ वसूली न होने पर भी 25 करोड़ रुपये तक के कर्ज को तुरंत एनपीए घोषित करने से बचाव के उपाय किए जाएंगे। कर्ज वसूली न होने पर जल्दी एनपीए घोषित नहीं करने से कुल कर्ज की तादाद तो बढ जायेगी परंतु एनपीए की वृद्धि नहीं होगी। यह बैंकों को ऊपरी तौर पर स्वस्थ दिखाने के लिये एक कवायद है।

'किसान मुक्ति की दिशा' में साक्षात्कार के ज़रिए भारतीय कृषि संकट को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार यह एक शाश्वत ढांचागत संवाद है जो हर तरह के किसान को प्रभावित करता है। यह एक ऐसा संकट है जो हमारे आर्थिक विकास के ढांचे में अन्तर्निहित है। आर्थिक संकट उत्पादन और उत्पादक दोनों का संकट है। सरकार दावा कर रही है कि 2017-18 के लिये सब फसलों के दाम बढा दिये हैं, परंतु सच यह है कि इस 'बढोतरी' में किसान के खुश होने लायक कुछ भी नहीं है। अपनी मांगो को मनवाने के लिये भूस्वामी, मंझौला व छोटा किसान, बटाईदार व खेतीहर मज़दूर सब एकजुट हो रहे हैं। उनकी प्रमुख मांगे हैं। कर्जा मुक्ति बिल पारित किए जाय तथा फ़सल की लागत का हिसाब बेहतर पद्धति से किया जाए जिससे लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत बचत सुनिश्चित हो जाए।

हरियाणा में चौटाला परिवार की लड़ाई ने राज्य की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के नए समीकरण के हालात पैदा कर दिये हैं, जिनकी '9 दिसम्बर से बदल सकता है हरियाणा का रानीतिक परिदृश्य-अजय और दुष्यंत चौटाला के बयानों ने गरमा दिया है राजनीतिक माहौल' में समीक्षा की गई है। इस प्रकरण में भाजपा, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, चौटाला परिवार के दोनों धड़े और आम आदमी पार्टी के विभिन्न समीकरणों के सम्भावनाओं का विश्लेषण किया गया है।

आरबीआई की सरप्लस पूंजी लेने के लिये मोदी सरकार द्वारा आरबीआई पर दबाव डालने तथा नोटबंदी के कारण नकदी के संकट पर 'आरबीआई-सरकार में मतभेद -ऐसा हमारे साथ नोटबंदी में होता था' कार्टून द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों पर उपयुक्त कटाक्ष किया गया है।